(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उत्पादों की उपलब्धता तथा बाटलिंग क्षमता सहित अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं होने पर तेल कम्पनियां नए उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार नए कनेक्शन जारी करती हैं। इसके अनुसार चरणबद्ध रूप से आर्थिक व्यवहार्यता के स्तर तक लाने के लिए नई वितरणशिपों के माध्यम से कनेक्शन जारी किए जाते हैं।

समापन प्रमाण-पत्रों का सत्यापन

849. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के एल पी जी विक्रेताओं को देश के विभिन्न भागों से उनको समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक समापन प्रमाण-पत्र जाली पाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी वास्तविकता का पता लगाने के लिए कोई जांच करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ प्राप्त टर्मिनेशन वाउचर (टी वी) जांच करने पर जाली पाए गए।

(ग) और (घ) जी, नहीं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कनेक्शन देने के बाद वितरक को टी वी की प्रमाणिकता की पुष्टि उसे जारी करने वाले वितरक से करानी होती है। यदि टी वी प्रामाणिक नहीं पायी जाती है तो तत्काल सप्लाई बंद कर दी जाती है और उपकरण प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं।

सन्त नगर, दिल्ली में बिजली की आपूर्ति

850. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन्त नगर, दिल्ली-110009 के निकट बुराड़ी गांव में बिजली की आपूर्ति नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1987-88 के दौरान सन्त नगर क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के संबंध में कोई प्रस्ताव हैं, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार बुराड़ी गांव पहले से ही विद्युतीकृत है। इस गांव की सन्त नगर कालोनी को ग्रामीण आबादी के रूप में अधिसूचित किया गया था और यह कालोनी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा 1986 में विद्युतीकृत की गई थी। सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संभावित उपभोक्ता बुराड़ी गांव और संत नगर में बिजली के कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

Exclusion of Duolut-on from Price Control Lists

851. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased o state :

(a) whether it is a fact hat Duoluton, Menstrogen, Ovral and Mixogen are not :overed under price control;

(b) whether it is also a fact that these are essential medicines;

(c) what was the sales turnover of each of these medicines dunng the last two yeais, year-wise;

(d) what aie the names of the bulk drugs of these medicines and what was the sales Uun-ovei of each during 1986; and

(e) on what grounds these drugs have not been included in the pi ice control lists ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) and (e) The bulk drugs on which the formulations referred to in the question

are based were not included by the Kelkar Committee in the list of Category-II drugs recommended for price control. Copies of the Kelkar Committee report are available in the Parliament Library.

(c) Sales turnover of formulations is not monitored.

(d) Information to the extent available is given in the attached Statement. *(See* below) Sales turn-over is not monitored.

Statement

SI. No.	Pre duct	Name cf the Bulk Drujt IPV{ lved
I.	Duoluton	Novgestrol Ethinyl Estradiol
2.	Menstrogen	Ethinyl Oestradiol Progestrone Ctbisterone
3.	Ovral	Novgestrol Ltninyl Oestradki
4.	Mixogen	Etninyl Oestradiol Testosterone

Issue of industrial licences

852. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased be state:

(a) the number of projects for which industrial licences have been issued during the current financial year, State-wise;

(b) the cost of each project;

(c) the number of licencees who have set up the industries so far; and

(d) the number of licencees who have not yet set up industries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL I DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRl M. ARUNACHALAM): (a) A statement is enclosed. *(See* below)

(b) Information regarding total cost involved in each project for which indus trial licences have been granted is not maintained centrally in the Secretariat for Industrial Approvals in (he Ministry of industry.

(c) and (d) An industrial licence is I granted with an initial validity period of two years within which the entrepreneur is expected to commence nrorinrtinn A- such, it is too early to make an assessment of the actual progress of implementation of the industrial licences granted during. the period April-September, 1987.

Statement

State-wise break-up of number of industrial Licences issued during the period April-September, 1987

SI. No.	State/Union Territory	Industrial Licences issued during April-September '87
1.	Andaman & Nicobar Islands •	
2.	Andhra Pradesh	17
3.	Arunacnal Pradesh	1
4.	Assam	2
J.	Bihar	3
6.	Chandigarh	2
7.	Dadra* Nagar Have	2
8.	Delhi	6
9.	Goa. Daman & Diu	1
10.	Gujarat	25
11.	Haryana	8
12.	Himachal Pradesh	1
13.	Jammu & Kashmir	4
14.	Karnataka	28
15.	Kerala	5
16.	Lakshadweep	—
17.	Madfja Pradesh	8
18.	Mahrashtra	41
19.	Manipur	—
20.	Meghalaya	—
21.	Mizoram	—
22.	Nagaland	—
23.	Orissa	4
24.	Pondicherry	—
25.	Punjab	
26.	Rajasthan	*9*
27.	Sikkim	—
28.	Tamil Nadu	17
2 9.	Tripura	—
3f,	UttarPradesh	19
31.	West Bengal	12
32.	More than one State / State not indicated	4
	TOTAL	229